

संपादकीय

चुनावों में खेल का मैदान विषम

कंपनियों को विजापन देकर कॉर्पोरेट क्षेत्र को लाभ पहुंचाएगा। चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक घोषित करने वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक ऐतिहासिक क्षण है। फिर भी, पाँच वर्षों के लिए समय के बाद आया यह निर्णय हमारे लोकतंत्र को संकट में डाल देता है। यदि मामले को चुनावी दिए जाने पर निर्णय दिया गया होता, तो भाजपा अपने पास मौजूद अकूत संपत्ति इकट्ठा नहीं कर पातीय फैसले के बावजूद, इसने हमारी राजनीति में एक गैर-स्तरीय खेल का मैदान तैयार कर दिया है। यह निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट है। साल 2018–19 और 2022–23 के बीच बीजेपी ने करीब 6,566 करोड़ रुपये जुटाए हैं। 2017–18 में, योजना शुरू होने से पहले, भाजपा को चेक के माध्यम से योगदान अपेक्षित नगण्य 210 करोड़ रुपये था। जनवरी 2018 में शुरू की गई योजना के अनुसार, भाजपा के पक्ष में जारी किए गए चुनावी बांड के माध्यम से योगदान 1,450 करोड़ रुपये तक बढ़ गया। यह भी स्पष्ट है कि मेरे मित्र स्वर्गीय अरुण जेटली द्वारा शुरू की गई योजना भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई थीयं इसके परिणामस्वरूप अंततः लोकसभा चुनावों और लगातार विधानसभा चुनावों के द्वारा एक गैर-स्तरीय खेल का मैदान बन गया। हम जानते हैं कि बदलते तारीफ और निष्क्रिय चुनाव हमारे संवर्चन व्यायालय द्वारा माना गया है। ऐसा भारत के स्वर्च्च न्यायालय द्वारा माना गया है। जिस समय चुनावी बांड योजना शुरू की गई थी, उस समय भारत निर्वाचन आयोग ने इसका विरोध किया था। इसके विरोध को खारिज कर दिया गया। जब तक इस मामले पर अदालत में बहस हुई, चुनाव आयोग, जो कार्यवाही में एक पक्ष था, ने चुप्पी साथ रखी थी। इसलिए, यह स्पष्ट है कि आयोग इस मामले में सरकार के साथ जाने के तौर पर था, हालांकि चुनावी प्रक्रिया में समान अवसर सुनिश्चित करना उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग को आवश्यक हमें अब आश्वर्यवाचिक नहीं करता है, यह देखें हुए कि उसने लगातार चुनावों के द्वारा उत्पन्न होने वाले सभी मुद्दों पर सरकार के साथ सक्रिय रूप से सहयोग किया है। फिर भी यह सुनिश्चित करना आयोग की जिम्मेदारी है कि आगामी लोकसभा चुनाव स्वतंत्र और निष्क्रिय हों। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया है, तो कानूनी तौर पर, भाजपा को हस्तांतरित धन, चाहे वह कोई भी हो, वैध नहीं माना जा सकता है। कानूनन, की गई अवैधता से भाजपा को लाभ नहीं होना चाहिए। हम यह उम्मीद करना मूर्खतापूर्ण स्वर्ग में जो रहे होंगे कि चुनावी आयोग भाजपा के साथ-साथ अच्युत राजनीतिक दलों को योजना के माध्यम से हस्तांतरित धन के अनुसार प्राप्त लाभों को खट्टम करने का निर्देश देगा। इसलिए, हम सत्ता में राजनीतिक दल को अनुचित लाभ देने वाली निरंतर, गैर-स्तरीय खेल के मैदान की स्थिति का सामना कर रहे हैं। परिणामस्वरूप, प्रतिस्पर्धियों को बिना किसी उपाय के नुकसान उठाना पड़ता है। संवैधानिक दृष्टि से यह स्थिति अस्थिर है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस योजना को असंवैधानिक घोषित करने का एक और परिणाम सामने आया है। अपने फैसले में, अदालत ने सही ही माना है कि एक राजनीतिक दल को कॉर्पोरेट क्षेत्र का भारी योगदान शायद शुद्ध उदारता का कार्य नहीं है। जिन लोगों ने इस योजना के माध्यम से पार्टी में योगदान दिया, उन्होंने शायद बदले की उम्मीद में ऐसा किया। चूंकि इन योगदानों का बड़ा हिस्सा 1 करोड़ के मूल्य के चुनावी बांड के माध्यम से था, दानकर्ता ऐसे उदाहरण से लाभ की उम्मीद करने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति या संस्थाएं होनी चाहिए। आज की परिस्थितियों में, और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने अपराध की आय और मनी लॉन्ड्रिंग की बीच अंतर को खत्म कर दिया है, तो प्रवर्तन निदेशालय, जो एक अति-सक्रिय और अति-उत्साही एजेंसी है, से अपेक्षा की जाती है। और जब दानकर्ताओं के नाम सामने आए, तो उन व्यक्तियों या संस्थाओं पर तुरंत छापा मारा जाए, जिन्होंने बदले की राशि, यदि कोई हो, तो पता लगाने के लिए योगदान दिया है। किसी भी मामले में, प्रवर्तन निदेशालय के सरकार का सत्ता में राजनीतिक दल के सदस्यों को निशाना बनाने के लिए नहीं जाना जाता है, जिनके रिकॉर्ड दागदार हैं। ऐसा होने की संभावना है कि जिन राज्यों में विपक्ष सत्ता में हैं, वहां एक बार एकआईआर दर्ज होने के बाद, प्रवर्तन निदेशालय तुरंत दान देने वाले विपक्षी नेताओं और कपनियों पर छापेमारी शुरू कर देगा और इस प्रक्रिया में मामला और भी गंदा हो जाएगा। अब जब इस योजना के तहान लाभ पाकर भाजपा को अनुचित लाभ हुआ है, तो यह एक वास्तविक डर है। इसलिए, यह स्थिति भाजपा को दोहारा एक बार देती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी कई कारोंगों से इस योजना पर आपति जताई थी। किसी को आश्वर्य हो सकता है कि आगामीआईआर अब क्या करेगा क्योंकि इस योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। हमारी राजनीतिक दलों को होने वाले नुकसान की सीमा केवल गैर-स्तरीय खेल मैदान के निर्माण तक ही सीमित नहीं है। स्थिति कहीं अधिक गंभीर है। कॉर्पोरेट क्षेत्र, जिसके बारे में कोई यह मान सकता है कि वह केंद्र में सत्तारूप पार्टी के लिए योगदान देता है, साथ ही पैमाने पर संपूर्ण मुख्यालय मीडिया का भी मालिक है।

कांग्रेस खुद पर अफसोस करे या गुरसा करे

आदित्य

कांग्रेस खुद पर अफसोस या गुरसा करे, अहंकार की दौलत में बिक रहा जमाना। जाहिर है हिमाचल से राज्यसभा की यात्रा ने एक सरकार के वजूद को छोला दिया और इस छिलाल भरे में सारी खुनरानी निकल गई। राजनीति अपनी बस्ती तो आया नहीं चुन सकती, तो अपनी ही अधिक उठानी पड़ी, वरना जानवर के कुल 25 विधायिकों के सामने कांग्रेस के चालीस इतने सक्षम थे कि अभिषेक मनु संघवीय हयां से राज्यसभा का तिलक लगाकर लौटे, मगर लुटिया ढूँढ़ी जानवर के द्वारा खाया। यह भी स्पष्ट है कि मेरे मित्र स्वर्गीय अरुण जेटली द्वारा शुरू की गई योजना भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई थीयं इसके परिणामस्वरूप अंततः लोकसभा चुनावों और लगातार विधानसभा चुनावों के द्वारा एक गैर-स्तरीय खेल का मैदान बन गया। हम जानते हैं कि बदलते तारीफ और निष्क्रिय चुनाव हमारे संवर्चन व्यायालय द्वारा माना गया है। ऐसा भारत के स्वर्च्च न्यायालय द्वारा माना गया है। जिस समय चुनावी बांड योजना शुरू की गई थी, उस समय भारत निर्वाचन आयोग ने इसका विरोध किया था। इसके विरोध को खारिज कर दिया गया। जब तक इस मामले पर अदालत में बहस हुई, चुनाव आयोग, जो कार्यवाही में एक पक्ष था, ने चुप्पी साथ रखी थी। इसलिए, यह स्पष्ट है कि आगामी लोकसभा चुनावों और लगातार विधानसभा चुनावों के द्वारा एक गैर-स्तरीय खेल का मैदान तैयार कर दिया है। यह भी स्पष्ट है कि अभिषेक मनु संघवीय हयां से राज्यसभा की जिला की दौलत को अपनी ही दौलत नहीं बदली, वरना जिले की दौलत को अपनी ही दौलत नहीं बदली। आश्वर्य यह कि सरकार के बीच खेले राजिंद्र राणा, सुधीर शर्मा व राजिंद्र राणा के बीच खेले राजिंद्र राणा, जिसने दूसरे तारीफ द्वारा बन गया। अभिषेक मनु संघवीय हयां से राज्यसभा की जिला की दौलत को अपनी ही दौलत नहीं बदली, वरना जिले की दौलत को अपनी ही दौलत नहीं बदली। आश्वर्य यह कि सरकार के बीच खेले राजिंद्र राणा, सुधीर शर्मा व राजिंद्र राणा के बीच खेले राजिंद्र राणा, जिसने दूसरे तारीफ द्वारा बन गया। अभिषेक मनु संघवीय हयां से राज्यसभा की जिला की दौलत को अपनी ही दौलत नहीं बदली, वरना जिले की दौलत को अपनी ही दौलत नहीं बदली। आश्वर्य यह कि सरकार के बीच खेले राजिंद्र राणा, सुधीर शर्मा व राजिंद्र राणा के बीच खेले राजिंद्र राणा, जिसने दूसरे तारीफ द्वारा बन गया। अभिषेक मनु संघवीय हयां से राज्यसभा की जिला की दौलत को अपनी ही दौलत नहीं बदली, वरना जिले की दौलत को अपनी ही दौलत नहीं बदली। आश्वर्य यह कि सरकार के बीच खेले राजिंद्र राणा, सुधीर शर्मा व राजिंद्र राणा के बीच खेले राजिंद्र राणा, जिसने दूसरे तारीफ द्वारा बन गया। अभिषेक मनु संघवीय हयां से राज्यसभा की जिला की दौलत को अपनी ही दौलत नहीं बदली, वरना जिले की दौलत को अपनी ही दौलत नहीं बदली। आश्वर्य यह कि सरकार के बीच खेले राजिंद्र राणा, सुधीर शर्मा व राजिंद्र राणा के बीच खेले राजिंद्र राणा, जिसने दूसरे तारीफ द्वारा बन गया। अभिषेक मनु संघवीय हयां से राज्यसभा की जिला की दौलत को अपनी ही दौलत नहीं बदली, वरना जिले की दौलत को अपनी ही दौलत नहीं बदली। आश्वर्य यह कि सरकार के बीच खेले राजिंद्र राणा, सुधीर शर्मा व राजिंद्र राणा के बीच खेले राजिंद्र राणा, जिसने दूसरे तारीफ द्वारा बन गया। अभिषेक मनु संघवीय हयां से राज्यसभा की जिला की दौलत को अपनी ही दौलत नहीं बदली, वरना जिले की दौलत को अपनी ही दौलत नहीं बदली। आश्वर्य यह कि सरकार के बीच खेले राजिंद्र राणा, सुधीर शर्मा व राजिंद्र राणा के बीच खेले राजिंद्र राणा, जिसने दूसरे तारीफ द्वारा बन गया। अभिषेक मनु संघवीय हयां से राज्यसभा की जिला की दौलत को अपनी ही दौलत नहीं बदली, वरना जिले की दौलत को अपनी ही दौलत नहीं बदली। आश्वर्य यह कि सरकार के बीच खेले राजिंद्र राणा, सुधीर शर्मा व राजिंद्र राणा के बीच खेले राजिंद्र राणा, जिसने दूसरे तारीफ द्वारा बन गया। अभिषेक मनु संघवीय हयां से राज्यसभा की जिला की दौलत को अपनी ही दौलत नहीं बदली, वरना जिले की दौलत को अपनी ही दौलत नहीं बदली। आश्वर्य यह कि सरकार के बीच खेले राजिंद्र राणा, सुधीर शर्मा व राजिंद्र राणा के बीच खेले राजिंद्र राणा, जिसने दूसरे तारीफ द्वारा बन गया। अभिषेक मनु संघवीय हयां से राज्यसभा की ज

